(ख) तथा (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [देखिए परिशिष्ट १०, अनुपत्र संख्या ४१ ।]

†[THE DEPUTY MINISTER FOR PRODUCTION (SHRI SATISH CHANDRA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement is laid on the Table of the House. [See Appendix X, Annexure No. 41.]

श्री कृष्णकान्त व्यास: क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए इन संस्थाओं को कच्चा माल भी देती है ?

श्री सतीश चन्द्र : यह प्रश्न तो आपने शिक्षकों की ट्रेनिंग के बारे में पूछा था। जितनी भी यह संस्थाएं हैं वे शिक्षक तैयार करती हैं।

श्री कृष्णकान्त व्यास: क्या मध्य भारत की किसी संस्था ने कुटीर उद्योग में प्रशिक्षण पाने के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया था ?

श्री सतीश चन्द्र : जिन स्थानों पर यह शिक्षा दी जा रही है वह इस विवरण में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी है तो नोटिस की आवश्यकता है ?

DR. P. C. MITRA: What are these institutes and where are they situated?

MR. CHAIRMAN: Please look at the statement.

SHRI SATISH CHANDRA: A long statement has been laid on the Table.

SHRI D. NARAYAN: May I know how many institutions are directly conducted by the Government?

SHRI SATISH CHANDRA: There are several institutions. There is one Central Institute at Nasik which has been established by the Cottage and Village Industries Board. Then there are six regional institutes which have been set up or are in the process of being set up. There is also a Central Pottery Institute. The handicrafts Board also runs one or two institutes to train people in different industries.

SHRI D. NARAYAN: Where are these six institutes to be started?

SHRI SATISH CHANDRA: In the different States.

SHRI D. NARAYAN: Yes, but which States and in which places?

SHRI SATISH CHANDRA: One is to be started at Sabarmati and one at Wardha.

PROF. G. RANGA: We have already got one there.

SHRI SATISH CHANDRA: One at Sevapuri. Banaras, and another at Nilokheri. I do not remember the exact locations of other regional institutes.

श्री कृष्णकान्त व्यास: क्या कुटीर उद्योगों के लिए मशीनें निर्माण करने का कोई केन्द्र है ? यदि है, तो वहां मशीनें तैयार होती हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: कुटीर उद्योगों में कोई बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं होती । जो छोटे छोटे औजार, इम्प्लीमेंट्स या टूल्स की जरूरत होती हैं वे बहुत से वर्कशाप्स में तैयार होते हैं । उत्तर देने में कठिनाई यह है कि यह प्रश्न सिर्फ शिक्षण के बारे में है।

काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ के सैनिक प्रेक्षक

*१९६. **श्री कृष्णकान्त व्यास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आजकल काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने कितने सैनिक प्रेक्षक किस किस देश के हैं ;

(ख) उन पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है

†English translation.

(ग) क्या वे संयुक्त राष्ट्र संघ को नियमित अवधि के अन्तर से कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन प्रतिवेदनों की प्रतिलिपियां भारत और पाकिस्तान की सरकारों को भेजी जाती हैं?

†[U.N. MILITARY OBSERVERS IN KASHMIR

*189. SHRI KRISHNAKANT VYAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the country-wise strength of the United Nations Military Observers working in Kashmir at present;

(b) the annual expenditure incurred on them;

(c) whether they submit any reports to the United Nations Organisation at regular intervals; and

(d) if so, whether the copies of the reports are also sent to the Governments of India and Pakistan?]

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) आजकल काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के दोनों तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ के फौजी प्रेक्षकों की देशवार संख्या नीचे दी गई है:

आस्ट्रेलिया	६
यूरूग्वे	३
चाइल	३
कनाडा	६
बेल्जियम	३
डेन्मार्क	२
न्यूजीलैंड	३
कुल	२६

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ के फौजी प्रेक्षक दल का खर्च संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया जाता है। लेकिन भारत सरकार कुछ सुविधाएं जैसे मुफ्त पेट्रोल और तेल, यातायात और डाक्टरी इलाज देती है। इसके अलावा, सीमा के इलाकों में यानी श्रीनगर और जम्मू से परे, ये प्रेक्षक वहां पर रहने वाली भारतीय फौजी टुकड़ियों के मेहमान होते हैं। इनके लिए जम्मू और काश्मीर राज्य क्षेत्र में काम करने वाले अफसरों पर लागू किए गए ढंग पर ही मुफ्त खाने और रहने का प्रबन्ध किया जाता है। इन सुविधाओं के खर्च का ब्यौरा नहीं मिला है।

(ग) और (घ), दोनों में से किसी सरकार द्वारा, युद्ध विराम समझौते के भंग होने पर दी गई रिपोर्ट के आधार पर, इन प्रेक्षकों का फैसला, भारत और पाकिस्तान की सरकारों को भेज दिया जाता है। यह नहीं मालूम कि ये प्रेक्षक संयुक्त राष्ट्र संघ को निश्चित समय में कोई रिपोर्ट भेजते हैं।

†[THE DEPUTY MINISTER FOR EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ANIL K. CHANDA): (a) The present country-wise strength of United Nations Military Observers in Kashmir on both sides of the Cease-fire Line is as under:

Australia	6
Uruguay	3
Chile	3
Canada	6
Belgium	3
Denmark	2
New Zealand	3
TOTAL	26

(b) The expenditure on the maintenance of the United Nations Military Observers Group is borne by the United Nations. The Government of India, however, provide certain facilities such as free petrol and oil transport and medical treatment. In addition, Observers in forward areas *i.e.* outside Srinagar and Jammu are treated as guests of the Indian army units stationed there and are provid-

†English translation.

ed free accommodation and rations at the scale applicable to officers serving in the Jammu and Kashmir State area. Particulars of the cost of these facilities are not available.

(c) and (d). The findings of the Observers on violations of the Cease-fire Agreement reported to them by either Government are forwarded to the Governments of India and Pakistan. It is not known whether the Observers submit any reports to the United Nations Organisation at regular intervals.]

श्री कृष्णकान्त व्यास: क्या संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक भारत और पाकिस्तान की सरकारों को इन रिपोर्टों की प्रतियां देते हैं ?

SHRI ANIL K. CHANDA: Reports are given to us.

श्री जवाहरलाल नेहरू: अगर कोई वाकया हुआ और उस वाकये की उन्होंने जांच की, तो उसकी रिपोर्ट हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के पास वे सीधे भेज देते हैं। लेकिन और अपनी मामूली रिपोर्ट वे संयुक्त राष्ट्र को भेजते हैं या नहीं, यह हम को मालूम नहीं है।

श्री कृष्णकान्त व्यास: क्या भारत और पाकिस्तान की सरकारें इस सम्बन्ध में कुछ कर सकती हैं कि अमुक अमुक देश के प्रेक्षक भेजे जाएं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: यह तो संयुक्त राष्ट्र के चुनने का काम है। वे ज्यादा से ज्यादा हमसे कभी कह देते हैं कि इसको हम चुन रहे हैं।

SHRI B. GUPTA: May I know what are now the functions of these United Nations Military Observers there; and whether such functions are really consistent with our national interest and sovereignty?

SHRI JAWAHARLAL NEHRU: Their functions are to look after the cease-fire line and to see that there is no violation of the cease-fire line. And this is completely consistent with what we have agreed to.

श्री कृष्णकान्त व्यास : क्या मैं प्रधान मंत्री से पूछ सकता हूं कि युद्ध बन्दी सीमा के इस ओर कितने प्रेक्षक हैं और उस ओर कितने हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: वे कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं।

श्री कृष्णकान्त व्यास: क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ पता है कि ये प्रेक्षक कब तक काम करते रहेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जी नहीं, नहीं पता है।

SHRI S. MAHANTY: May I know whether the U. N. Observers have submitted any report to the Government of India on the Neokwal firing on the Jammu-Kashmir border?

SHRI JAWAHARLAL NEHRU: Yes, as the hon. Member knows, because there has been a great deal of reference to it in the Press, although a full report is not published, because it is for the United Nations to publish it, we cannot publish their documents. But a summary of it has appeared in the Press.

SHRI S. MAHANTY: May I know what are the broad contents of that report? It is a matter of vital importance.....

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Mahanty; but they submitted the report to the United Nations and I presume that it is for the U. N. to publish it.

SHRI S. MAHANTY: No, Sir.....

SHRI JAWAHARLAL NEHRU: No, they submitted the report to Pakistan and to the Government of India, and no doubt, to the United Nations. But we are not supposed to publish their reports as such In fact, a summary of the report containing their main conclusions has been published in the Press.

SHRI S. MAHANTY: Most respectfully I would like to submit that whenever such matters of importance come up, Government does not take notice of matters published in the Press. We are not now concerned with what is published in the Press. In the latter part of the answer it has been said that reports are also submitted to the Government of India. I wish to know from the reports which have been submitted to the Government of India, on which party have they laid the blame for this most unfortunate incident?

SHRI V. K. DHAGE: And what has been the result?

SHRI JAWAHARLAL NEHRU: The hon. Member will forgive me if I express my surprise on his ignorance of this matter, because Government have issued an official communique. When I said it is published in the Press, it is not a press surmise that I mean but an official communique. And that report laid the blame entirely on the Pakistan side.

SHRI S. MAHANTY: May I know, then whether the Government of India is claiming any compensation for the firing?

SHRI JAWAHARLAL NEHRU: Yes, the Government of India did claim compensation as well as punishment of those who were found to have been guilty of misbehaviour.

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी

*१९०. **श्री कृष्णकान्त व्यास**: क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री २३ फरवरी १९५५ को राज्य सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न नं० ६ के उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि पंच-वर्षीय योजना के प्रचार के लिए प्रत्येक क्षेत्र में तब से क्या और क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नियुक्त किए गए हैं?

†[REGIONAL PUBLICITY OFFICERS

*190. SHRI KRISHNAKANT VYAS: Will the Minister for INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the reply given to unstarred question No. 6 in the Rajya Sabha on the 23rd February, 1955 and state whether any more regional publicity officers have since been appointed in each region for the publicity of the Five Year Plan?]

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० बी० वी० केसकर): जी हां, तब से एक और क्षेत्रीय पब्लिसिटी आफिसर की नियुक्ति हुई है और वह मध्यवर्ती क्षेत्र यानी सेंट्रल रीजन के लिए हुई है। उसका दफ्तर हैदराबाद में होगा। बची हुई एक जगह के लिए नियुक्ति करने का विचार हो रहा है।

†[THE MINISTER FOR INFORMATION AND BROADCASTING (DR. B. V. KESKAR): Yes, one more Regional Officer has since been appointed with Headquarters at Hyderabad for the Central Region. The appointment to the remaining one post is still under consideration.]

श्री कृष्णकान्त व्यास: इन अधिकारियों के प्रमुख काम कौन कौन से हैं?

श्री जी० राजगोपालन: फाइव ईयर प्लान की पब्लिसिटी करना।

श्री कृष्णकान्त व्यास: इनकी नियुक्तियों में कौन सी योग्यता मानी गई है?

श्री जी० राजगोपालन: पब्लिक सर्विस कमीशन सिलेक्ट करता है।

श्री कृष्णकान्त व्यास: मध्य भारत के लिए भी क्या क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो कहां उसका हेडक्वार्टर है?

†English translation.